आईआईटी कैम्पसों में प्लेसमेंट सीजन की धूम।

किन्तु हजारों इंजीनियरिंग कालेजों में हालात ठीक नहीं हैं।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

पिछले 9 महिनों के कोविड काल में उद्योग धंधों और कारोबार में अभूतपूर्व गिरावट देखने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से उठ खड़े होने के संकेत दे रही है। यूँ तो इसके संकेत कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में देखे जा रहे हैं, किन्तु इस का एक अन्दाज इस बात से भी लगाया जाता है कि देश के कालेजों व यूनिवर्सिटियों में इस साल प्लेसमेंट कैसे होंगे और युवा इंजीनियरों तथा एमबीए डिग्री धारियों को कैसी नौकरियाँ मिले।गी?

उच्च शिक्षा संस्थानों में अभी सभी काम धीरे–धीरे शुरू हो रहे हैं। अभी तक पठन–पाठन का काम ऑनलाइन कक्षाऐं लगा कर किया जा रहा था, किन्तु अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि कैम्पस में फिर से विद्यार्थी कब लौटेंगे? किन्तु देश के शीर्षस्थ इंजीनियरिंग एवं प्रबंध संस्थानों में प्लेसमेंट की हलचल शुरू हो चुकी है। 1 दिसंबर, 2020 से पुराने आईआईटी संस्थानों में वर्चुअल ढंग से प्लेसमेंट का सीजन शुरू हो चुका है। इसकी तैयारियां कई महिनों से चल रही थीं। पहले की तरह कंपनियों के प्रतिनिधि विद्यार्थियों को इन्टरव्यू और चयन करने के लिये कैम्पस में नहीं आये।

आईआईटी, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और दिल्ली से जो प्लेसमेंट की खबरे आ रही हैं, उन से लग रहा है कि नियोक्ता कम्पनियों में कोविड से पैदा हुए आर्थिक ठहराव के बावजूद कोई पस्तहिम्मती नहीं दिख रही है।

इंजीनियरिंग में आईआईटी संस्थान देश में ही नहीं वरन् विश्व भर में अपनी बेहतरीन शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण धाक जमा चुके हैं। नियोक्ताओं के लिये आईआईटी और आईआईएम सब से ज्यादा आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। देश में वैसे तो आईआईटी संस्थानों की संख्या 23 हो चुकी है किन्तु पुराने और नये संस्थानो की ख्याति और प्रतिष्ठा में फर्क रहता है। वर्ष 1951 में आईआईटी, खड़गपुर का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने किया था तो उन्होनें अपने भाषण में उम्मीद जताई थी कि ये संस्थान एक दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की नींव बनेंगे। आज इस सपने के सच होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

आईआईटी, खड़गपुर की तरह आईआईटी, मुंबई इंजीनियरिंग के शीर्ष संस्थानों में गिना जाता है। इस की स्थापना 1958 में हुई थी और यहाँ प्लेसमेंट के लिये देश–विदेश की बड़ी–बड़ी कंपनियां हर साल आती है। प्लेसमेंट के पहले दिन ही माइक्रोसोफ्ट, गूगल, एपल, बेन, टैक्सास इन्स्ट्रूमेंट, क्वालकोम, बीसीजी जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों को देखा गया। 2020–21 के प्लेसमेंट सीजन के प्रथम दो दिन में 35 कंपनियों ने 400 नौकरियां बांटी और सोनी,

जापान ने रू. 1.63 करोड (करीब रू. 13 लाख मासिक) का वार्षिक पैकेज दिया जो सर्वाधिक रहा।

अगले कुछ महिनों तक करोड़ो रूपये के पैकेज दिये जाने की खबरें अखबारों और टीवी चैनलों पर चर्चा का विषय बनती रहेंगी। किन्तु हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिये कि इस तरह की मोटी तनख्वाह सभी आईआईटी संस्थानों में विद्यार्थियों के बड़े वर्ग को मिलती होंगी। मिसाल के तौर पर आईआईटी, मुंबई का औसत पैकेज इस बार अभ तक रू 16.06 लाख वार्षिक रहा है जो कि पिछले साल रू. 20.08 लाख था। आईआईटी, मुंबई का वार्षिक पैकेज ऊंचा रहने का कारण बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियों का प्लेसमेंट में शामिल होना है। इस बार यहाँ 159 विदेशी कंपनियों ने नौकरियां दी हैं।

लेकिन करोड़ रूपये के पैकेज मिलने की उत्सावर्धक खबरों से हमे उन तथ्यों से आखें नहीं मोढ़नी चाहिये जो कि भारत उच्च शिक्षा के कटु विरोधाभासों को उजागर करती हैं। देश के 4800 इंजीनियरिंग कालेजों में सभी जगह यह नजारा नहीं मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग–शिक्षा में संकट लगातार बड़ा है उसके कई कारण हैं। सैंकड़ो इंजीनियरिंग कॉलेज या तो बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने के कगार पर हैं। एआईसीटीई भी अपनी नीति के तहत उन कालेजों की मान्यता रद्द कर रही है जो कि न्यूनतम संख्या में दाखिले नहीं कर पा रहे हैं।

वर्तमान में देश के 4800 इंजीनियरिंग कालेजो में करीब 15 लाख सीटें हैं। सवाल यह है कि भारत की इंजीनियरिंग शिक्षा में ऐसी स्थिति क्यो आई? वर्ष 2007 तक देश में इंजीनियरिंग कालेज धड़ाधड़ खोले जा रहे थे किन्तु 2008 की विश्वव्यापी मंदी के बाद इस में अचानक ब्रेक लग गया। पिछला दशक (2010–2020) इंजीनियरिंग शिक्षा में मंदी का दौर की कहा जायेगा। अब हम अगर रोजगार के बाजार में इंजीनियरिंग की नौकरियों के रूझान की बात करें तो सिर्फ कम्पूटर साइंस और आईटी जैसी ब्रांचों में ही नौकरियां बड़ी संख्या में मिल रही हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रीकल और कैमीकल इंजीनियरिंग में न तो दाखिले हो रहे और न ही नौकरियां मिल रही हैं।

देश के हजारों इंजीनियरिंग कालेज नियोक्ताओं और विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। ये कालेज दाखिले के समय जो भी वायदे करें किन्तु यहां विद्यार्थियों को छोटी–मोटी कंपनियों में रू. 15–20 हजार मासिक वेतन की नौकरियां ही मिल पाती हैं जिन में कैरियर बनाना और स्थायित्व मिल पाना मुश्किल होता है। इन कालेजों के पास न तो अच्छे शिक्षक हैं और नहीं ये ऐसी जगहों पर स्थित हैं, जहां नजदीक में उद्योग–धंधे चल रहे हों।

आईआईटी संस्थानों की श्रेष्ठ गुणवत्ता सराहनीय है किन्तु भारत की इंजीनियरिंग शिक्षा का यह एक बहुत छोटा हिस्सा है। वर्ष 2019 तक सभी 23 आईआईटी संस्थानों में 11,277 सीटें थीं जो कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने वाले 0.6 प्रतिशत परीक्षार्थियों को ही मिल पाई।

ज्ञातव्य है कि हर साल करीब 9 लाख विद्यार्थी जेईई परीक्षा में अपने भाग्य की आजमाइश करते हैं। वर्ष 2020 में 8.58 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई का आवेदन पत्र भरा था किन्तु कोविड के कारण 6.35 लाख (74 प्रतिशत) ही परीक्षा दे पाये।

देश के 4800 इंजीनियरिंग कालेजों में प्लेसमेंट कुछ महिने बाद शुरू होंगे। देखना है कि आईटी कंपनियां एवं अन्य क्षेत्रों की कम्पनियां इस बार कितने युवा इंजीनियरों को इस बार रोजगार दे पाती हैं? आज की परिस्थितियों में जरूरी है कि केन्द्र सरकार कारपोरेट जगत के नेताओं से बात करे और उन्हें इस बात के लिये राजी करे कि लाखों इंजीनियरों को रोजगार दिये जा सकें। क्यो वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन कोई ऐसी वित्तिय योजना घोषित कर सकती है कि सिर्फ इस साल जो कंपनी इंजीनियरों को भर्ती करे उन्हें उस के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। बी.टेक. परीक्षा पास करने वाले लाखों विद्यार्थियों में बहुतायत में विद्यार्थियों के ऊपर एजूकेशनल लॉन की देनदारी बकाया होगी। जिन इंजीनियरों को रोजगार न मिल पाये उन के लोन भुगतान को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि उन्हें रोजगार न मिल पाये।

मानव संसाधन मंत्रालय को इंजीनियरिंग शिक्षा के पुनरूत्थान के लिये एक विशिष्ट योजना बनानी चाहिये। 90 के दशक में वर्ल्ड बैंक से इन कालेजों को आधुनिकीकरण के लिये कई वर्षों तक आर्थिक सहायता दी गई थी, जिस के अच्छे नतीजे देखने में आये थे। एक ही स्थान पर स्थित कई इंजीनियरिंग कालेजों को विलय कर एक मजबूत इकाई बनाना भी कारगर हो सकता हैं। इंजीनियरिंग संस्थान देश के भविष्य की आधारशिलाएँ हैं। 1950 एव 60 के दशकों में अगर आईआईटी संस्थान न बने होते तो आज हमारा आईटी उद्योग 100 बिलियन डॉलर के कारोबार के साथ विश्व भर में नामचीन नहीं होता।